

पाँचवा-सत्रम्

40
CUTS
International
1983-2023



हमारा मुख्य-पत्र

वर्ष 24, अंक 1/2023

सतत् उपभोग एवं उत्पादन के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए¹ मानव को अपनी जीवन शैली में लाना होगा बदलाव

‘कट्टस’ इंटरनेशनल, जयपुर द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जर्वेशन के सहयोग से राजस्थान में संचालित ‘सतत् उपभोग और जीवन शैली की संस्कृति का विकास’ (प्रोस्क्रोप) परियोजना के तहत राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए अजिताभ शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. ने कहा कि सतत् विकास के लक्ष्य-12 (सतत् उपभोग एवं उत्पादन) को सफल बनाने के लिए मानव को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कंपनियां केवल अपने शेयर होल्डर्स के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। भारत सरकार ने नई नीति बनाई है, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों को सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी।

कार्यक्रम में विजय शर्मा, रीजनल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के बहुत अधिक उपयोग से कच्चे माल की कीमतें बढ़ती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में अब रिसाइक्ल पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइक्ल करके फाइबर बनाना और फाइबर से कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से ठोस



कचरे से बिजली और ईंटे बनाए जाने का विकल्प कई कंपनियां लेकर आ रही हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में ‘कट्टस’ के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमर दीप सिंह ने बताया कि सतत् उपभोग एवं उत्पादन के विषय में भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के उपभोग करने के तरीकों में बदलाव आया है, जिसका पर्यावरण के साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘कट्टस’ विगत कई वर्षों से सतत् उपभोग के क्षेत्र में कई अध्ययन और परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। राजस्थान राज्य में भी सतत् उपभोग की संस्कृति को विकसित करने हेतु राजस्थान के सभी संभागों में एक परियोजना संचालित कर रहा है।

उन्होंने बताया कि ‘कट्टस’ द्वारा पूर्व में पांच राज्यों में सर्वेक्षण किया गया था। इसी तरह का सर्वेक्षण राजस्थान के सभी सात संभागों में 711 सैंपल लेकर किया गया। सर्वेक्षण में यह निकल कर आया कि अधिकतर लोग ई-वेस्ट कबाड़ी वालों को देते हैं। राजस्थान में बहुत कम रिसाइक्ल होता है। अतः सभी हितधारकों जैसे शहरी सरकार, विभिन्न विभाग, स्वयंसेवी

संस्थाएं, नागरिक संगठन, विकास समितियां आदि को साथ मिलकर काम करना होगा।

कार्यक्रम में स्थानीय निकाय विभाग की स्टेट नोडल पर्सन, स्वच्छ भारत मिशन की हिमानी तिवारी ने बताया कि राजस्थान में ठोस कचरा प्रबंधन अभी भी बड़ी चुनौती के रूप में है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत से प्रयास स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। विक्रम सिंह राघव, राज्य तकनीकी सलाहकार (एस.डी.जी.) पंचायती राज विभाग ने कहा कि सतत् विकास लक्ष्य 12 में सतत् उपभोग और उत्पादन को शामिल किया गया है। सतत् विकास के लिए सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक पहलुओं को सभी योजनाओं में जोड़ना जरूरी है। उपभोक्ताओं की प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर डॉ. सोमना दत्ता ने ‘शेयरिंग कम्यूनिटी’ के उदाहरण देते हुए शहरी क्षेत्र में इस भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए 50 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रियता से भाग लिया।

इस अंक में...

■ वसूला ग्रीन टैक्स, खर्च दूसरे कार्मों पर	3
■ भारत का विकास पूरी दुनिया के लिए अहम ...	5
■ देश बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब	8
■ बूंद-बूंद बचाएं पानी, घट रहा भूजल	9
■ महिलाओं को दी गई कई सहायिताएं	10

शहरी निकायों के क्षमतावर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित

‘कट्स’ द्वारा राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग तथा ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली के सहयोग से अजमेर में 17 मार्च 2023 को शहरी निकायों की क्षमतावर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुशील कुमार, आयुक्त, नगर निगम अजमेर ने कहा कि शहरी निकायों की क्षमतावर्धन के लिए समय-समय पर केपेसिटी बिल्डिंग कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि स्थानीय निकायों के अधिकारीण अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और नए-नए नवाचार कर अपने शहरी क्षेत्रों का विकास कर सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अन्य शहरों और स्थानीय निकायों का भ्रमण भी करवाया जाना आवश्यक है ताकि अन्य शहरों के बेहतरीन प्रयासों से सीखकर उन्हें अपने शहरों में लागू कर सकें।

कार्यक्रम में आलोक जैन, क्षेत्रीय उपायुक्त, स्थानीय निकाय विभाग ने कहा कि शहरी निकायों में सुधार के लिए हमें आम लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठोस कचरे के प्रबंधन, प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट, सीवरेज जैसी गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए आम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए व्यवहार परिवर्तन के प्रयास भी किए जाने की जरूरत है। क्षमतावर्धन कार्यक्रम में मुख्य रूप से निकायों के वित्तीय प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सतत परिवहन एवं सामुदायिक भागीदारी विषयों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में हैदराबाद ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विषय वशेषज्ञ डॉ. डी. सुधाकर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए।



अधिकारी कमलदीप शर्मा ने म्यूनिसिपल फाइनेंस विषय पर प्रतिभागियों को जानकारी दी तथा डॉ. हिमानी तिवारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा निकायों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में अजमेर संभाग के 30 से अधिक निकायों के अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्य स्तरीय परिवर्चन का आयोजन

क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से जैविक खेती करना ज्यादा असरदार-प्रो. बलराज सिंह

हरित क्रांति के समय देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी। उस समय खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों को बढ़ावा दिया गया था। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। आज की स्थिति में देश में खाद्यान्न का उत्पादन तो बहुत अधिक हो रहा है, परन्तु गुणवत्ता खराब हो गई है। अब देश में जैविक खेती का दौर शुरू हो रहा है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से जैविक खेती करना ज्यादा असरदार है।

उक्त विचार एस.के.एन. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर के कुलपति प्रो. बलराज सिंह ने ‘कट्स’ द्वारा स्वीडिश सोसायटी ऑफ नेचर कंजरवेशन के सहयोग से जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय परिवर्चन में व्यक्त किए। परिवर्चन के प्रारंभ में ‘कट्स’ के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि राजस्थान में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। जैविक खेती में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। उन्होंने बताया जैविक खेती के क्षेत्र में ‘कट्स’ पिछले दस वर्षों से काम कर रहा है तथा परियोजना के तहत राज्य के 12 ज़िलों में मॉडल जैविक ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने विभाग द्वारा जैविक खेती करने वाले किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया ने बताया कि जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र के गांव लापोडिया में संस्था द्वारा पानी बचाने के क्षेत्र में कार्य किया गया है। उचित मात्रा में पानी का संरक्षण करते हुए खेती की जा सकती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में ‘कट्स’ के सह निदेशक दीपिका सक्सेना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और परियोजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। ‘कट्स’ के राजदीप पारीक ने परियोजना के तहत आयोजित गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में 50 से अधिक किसानों, संस्था प्रतिनिधियों व कृषि अधिकारियों ने भाग लिया।





सरकारी टैक्स वसूली में लेटलतीफी

केंद्र सरकार लगातार प्रयासों के बाद भी टैक्स बकायादारों से 15.82 लाख करोड़ रुपए नहीं वसूल पा रही। बकाया राशि केंद्र सरकार के हाल ही पेश किए गए बजट आकार का करीब 30 फीसदी है। खास बात यह है कि इसमें से 3.80 लाख करोड़ रुपए पर कोई विवाद नहीं है।

इसके अलावा 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि अदालती या अन्य विवादों में फंसी है। सरकार यदि टैक्सपेर्यस से बकाया टैक्स वसूलने में सफल हो तो देश के विकास व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और गति मिल सकती है। लेकिन सच यह है कि लगातार प्रयासों के बाद भी टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही। इसकी वजह या तो बकायादार को तलाश नहीं पा रहे या उनके पास इतनी पर्याप्त संपत्ति नहीं है, जिससे वसूली हो सके। अदालती मामले भी जल्द सुलझें तभी वसूली संभव है। (रा.प., 17.02.23)

पोषाहार में हुआ करोड़ों का घोटाला

बच्चों के पोषाहार में घोटाला अप्रैल 2015 से जुलाई 2018 तक का है। इस अवधि में पंजीयी घोटाला हुआ था। घोटाले की भनक पर एसीबी ने जुलाई 2018 में छापेमारी की थी। इसकी लंबे समय तक चली जांच में करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला माना जा रहा है।

अब पोषाहार वितरण में करोड़ों की इस गड़बड़ी करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग नागौर के 12 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें 8 महिला सुपरवाइजर और 4 लीपिक शामिल हैं। घोटाले में शामिल 14 आरोपियों की अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। लेकिन दो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए 12 आरोपियों की ही अभियोजन की स्वीकृति मिल पाई है। इन्हें विभाग द्वारा सर्सेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर हुई। (दै.भा., 09.01.23)

देशभर में मिले फर्जी राशन कार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर की गई जांच में 55 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड या डुप्लिकेट लाभार्थी पाए गए हैं। इनमें से 60 फीसदी यानी करीब 33 लाख मामले 7 राज्यों में मिले हैं। तीन लाख से अधिक फर्जी मामले वाले राज्यों में उत्तरप्रदेश सबसे ऊपर है।

सूचना का है अधिकार! जवाबदेह होगी सरकार!!

वसूला ग्रीन टैक्स, खर्च दूसरे कामों पर

प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ग्रीन टैक्स लगाकर जनता से हर साल करोड़ों रुपए वसूल रहा है लेकिन यह पैसा सड़क, नाली, पुल व रोडवेज सहित कई निगमों का घाटा भरने में खर्च हो रहा है। पिछले पांच सालों में ग्रीन टैक्स से सरकार के खजाने में 11,186 लाख रुपए आए, लेकिन सरकार ने मात्र 51.43 करोड़ रुपए ही खर्च किए।



लगातार बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया गया, लेकिन हरियाली बढ़ाने वाले बन विभाग को इस टैक्स का पूरा पैसा नहीं मिल रहा। राशि के उपयोग का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होता है। यदि पूरा पैसा हरियाली बढ़ाने पर खर्च हो तो प्रदेश में कई नए पार्क विकसित हो सकते हैं। (रा.प., 03.03.23)

अन्य राज्यों में बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 3.06 लाख फर्जी राशन कार्ड मिले हैं। जो इन राज्यों में सबसे कम है। सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड 9.21 लाख उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि लाभार्थियों की सूची का राज्य सरकारें लगातार समीक्षा करती हैं और निरस्त लाभार्थियों की एवज में नए एवं पात्र लोगों के राशन कार्ड जारी होते हैं।

(दै.भा., 02.02.23)

लाल रक्त का काला कारोबार

प्रदेश के कुछ ब्लड बैंक इंसान की रगों में दौड़ने वाले लाल रक्त का भी 'काला' कारोबार करने में जुटे हैं। राजधानी जयपुर और ग्रामीण क्षेत्र के 4 ब्लड बैंकों में इतनी अनियमितताएं मिली है कि इनमें से 3 के लाइसेंस निलम्बित और एक का निरस्त कर दिया गया।

इन ब्लड बैंकों में मरीज की जान से खिलवाड़ करने वाली कई अनियमितताएं पाई गई हैं। एक ब्लड बैंक में तो गंभीर मरीजों को चढ़ाए जाने वाले सिंगल डोनर प्लेटलेट की मशीन ही निरीक्षण टीम को मौके पर नहीं मिली। तीन अन्य ब्लड बैंकों में भी मौके पर जरूरी संसाधन नहीं मिले। चार ब्लड बैंकों पर सख्त एक्शन लिया गया। अभी कुछ और ब्लड बैंकों की पड़ताल जारी है। (रा.प., 22.02.23)

एक साल से किसानों का बीमा नहीं

सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले प्रदेश के 28 लाख किसानों की ऋण राशि का बीमा सरकारी फाइलों में अटक गया है। सहकारी

विभाग और वित्त विभाग में अटकी फाइल के कारण किसानों का वर्ष 2022-23 में बीमा ही नहीं हुआ। वर्तमान में 8 लाख किसान बीमा से वंचित हैं। जबकि किसानों को ऋण देते समय ही बीमा का प्रीमियम काट लिया गया था।

वर्ष 2023-24 का मामला भी अभी अधर में है। बीमा का टेंडर करने के बाद मामला अब सहकारी विभाग के पास लंबित है। फाइल पर अंतिम निर्णय समय पर नहीं हुआ तो आठ लाख के बजाय ऋण लेने वाले सभी 28 लाख किसान बीमा से वंचित रह जाएंगे। बीमा नहीं होने से इस समय के अंतराल में जिन किसानों की मौत हो गई, कर्ज उस किसान के परिवार पर आ गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देती है। (रा.प., 27.02.23)

सवालों के घेरे में जलदाय विभाग

जयपुर जिला वृत्त ग्रामीण और जयपुर शहर में 2014 से 2021 तक पाइप निर्माता कंपनियों, इंजीनियरों और ठेकाफर्मों के गठजोड़ से पेयजल परियोजनाओं में करोड़ों रुपए के घटिया पाइप बिछाए गए थे। जलदाय विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा पाइपों के सैंपलों की जांच में पाइप घटिया होने की पुष्टि हुई है।

प्रकोष्ठ के इंजीनियरों ने जांच रिपोर्ट को दबा दिया और कंपनियां इसके बाद भी करोड़ों रुपए के पाइप पेयजल परियोजनाओं में आपूर्ति करती रहीं। अब आठ वर्ष बाद 6 पाइप निर्माता कंपनियां, ठेकाफर्मों और संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण) ने जारी किए हैं।

(रा.प., 22.01.23)



खाद्य सुरक्षा में लोगों करोड़ों की चपत

खाद्य सुरक्षा योजना में राशन के गेहूं परिवहन के टेंडर में लोक उपापन के नियमों की अनदेखी हो रही है। जयपुर जिले में डिपो से राशन की दुकानों तक गेहूं पहुंचाने के लिए जारी किए गए 7 करोड़ रुपए के टेंडर में गड़बड़ज़ाले की आशंका है। चहेती फर्म को टेंडर नहीं मिलने की आशंका के चलते जिला प्रबंधक ने तीन महीने तक टेंडर नहीं खोला।

अब वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर इसी टेंडर को परिवहन की कई गुना दरों पर चहेती फर्म को देने की तैयारियां की जा रही है। यह कारगुजारी सामने आने के बाद जयपुर जिला प्रबंधक अनिल गोयल को आरोप पत्र दिया गया है। उधर गेहूं परिवहन का नया टेंडर नहीं होने से एक महीने से गेहूं का उठाव नहीं हो रहा है। इससे लाभार्थियों को राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिल रहा। मामले की जांच बाकी है।

(रा.प., 11.03.23)

शहरी आजीविका मिशन में भेदभाव

राजस्थान सरकार एक तरफ आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीबों के फायदे के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन केंद्र प्रवर्तित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में भेदभाव बरत रही है।

मिशन के तहत प्रदेश में 3 लाख रुपए की सालाना आय वाले लाखों परिवारों के 29277

स्वयं सहायता ग्रुप बने हुए हैं। उनको मिशन से जुड़े लाखों परिवारों को संबल देने के लिए बजट मिलता है।

वर्ष 2022-23 में केंद्र ने तो अपना अंश 4366.95 लाख रुपए दे दिया, लेकिन राज्य हिस्से के करीब 40 करोड़ रुपए एक साल से नहीं दिए गए। प्रदेश में करीब 30 हजार स्वयं सहायता समूह इसका इंतजार कर रहे हैं। योजना का पैसा स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से जुड़े सभी परिवारों की मदद के लिए दिया जाता है।

(दै.भा., 12.03.23)

बिना काम के करोड़ों का खर्च?

कचरे के निस्तारण के लिए जर्मन तकनीक पर आधारित 15 करोड़ रुपए की लागत से बना प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट प्लांट खुद कबाड़ में तब्दील हो गया। इस प्लांट के जरिए सरकार ने इसको रोल मॉडल बताते हुए दावा किया था कि यहां हर दिन पाली शहर और सोजत सिटी के 200 टन कचरे से खाद व फायर ब्रिक्स बनाया जाएगा।

इसके लिए नई दिल्ली की रॉल्ज मेटेरियल हैंडलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल के लिए संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। फर्म ने 67 से ज्यादा मशीनों के बिल दिखाकर 11 करोड़ रुपए का भुगतान भी उठा लिया।

इनमें से ज्यादातर मशीनें अब प्लांट में मौजूद नहीं हैं। खेतावास स्थित प्लांट के पास खेतों में

उन्होंने कचरा फैल रहा है और जमीन बंजर हो रही है। नगर परिषद ने 26 अगस्त 2016 को कंपनी से प्रोसेसिंग व निस्तारण के लिए अनुबंध किया था, लेकिन फर्म काम नहीं कर रही है।

(दै.भा., 31.03.23)

कर्ज के दलदल में विकास का पहिया

विकास का पहिया कर्ज के दलदल में घुस रहा है। राज्यों ने अप्रैल-दिसंबर के बीच यानी 9 महीनों में जितना कर्ज लिया था, उससे 52 प्रतिशत ज्यादा तो जनवरी से मार्च के बीच लेने वाले हैं। 30 राज्यों ने अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान कुल 2.28 लाख करोड़ का कर्ज लिया था और जनवरी से मार्च 2023 में 3.40 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है।

पंजाब देश में सबसे बड़ा कर्जदार है। दूसरा नंबर राजस्थान का है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक किसी भी राज्य का कर्ज उसकी जीडीपी के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नतीजा यह है कि राज्यों की आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। यह हालात मुफ्त और गैर जरूरी खर्चों से बिगड़े हैं। राजस्थान पर जीडीपी का 40 प्रतिशत और पंजाब पर 53 प्रतिशत कर्ज है।

(दै.भा., 22.01.23)

राजस्थान में जमकर हो रहा अवैध खनन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में प्रदेश के खान विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि खान विभाग अवैध खनन के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग की कमियों के चलते राजस्थान को बड़ा राजस्व नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वीकृत खननपट्टों के नजदीक 122 प्रकरणों में 83.25 हेक्टेयर में अवैध खनन की पहचान की गई। 13 खनन पट्टों में खनिज निकाला ही नहीं गया, लेकिन 22,854 ई-रवनों का दुरुपयोग करके 5.20 लाख मीट्रिक टन खनिज की निकासी की गई। इसकी कीमत 16.64 करोड़ रुपए थी। अधिकारियों ने खनन पट्टों का निरीक्षण ही नहीं किया। सामने यह भी आया कि 53 प्रकरणों में मांग राशि 71.20 करोड़ रुपए को नहीं दिखाया गया था। भ्रष्टाचार के 22 हजार ई-रवना बनाए, पेनल्टी तक नहीं वसूली गई। ऐसे में करीब 100 करोड़ रुपए अफसर ही खा गए।

(दै.भा., 01.03.23)

अवैध खनन से हुआ करोड़ों का नुकसान

राज्य में हो रहे अवैध खनन के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी 31 मार्च 2021 तक की सालाना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सीएजी ने पाया कि प्रदेश में 13.37 लाख टन खनिजों का अवैध खनन हुआ है, जिसकी कीमत 1.11 अरब रुपए है। देश में सर्वाधिक संख्या में खनन पट्टे राजस्थान में हैं।



कैग ने पाया कि इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। विभाग ने खनन की नई तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग डाटा एवं जीआईएस का उपयोग ही नहीं किया। लेखापरीक्षा ने रिपोर्ट सेंसिंग डाटा एवं जीआईएस तकनीक के उपयोग से 122 प्रकरणों में 83.25 हेक्टेयर में अवैध खनन की पहचान की है। यह परिणाम दर्शाते हैं कि 34 प्रतिशत खनन पट्टों के निकट अवैध खनन हो रहा था।

(रा.प., 01.03.23)



भारत का विकास पूरी दुनिया के लिए अहम

यूएई में होने वाले सीओपी-28 के लिए मनोनीत अध्यक्ष डॉ. सुल्तान अल जाबेर ने कहा है कि भारत का टिकाऊ विकास न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है।

पर्यावरण संरक्षण मजबूरी नहीं

दिल्ली में आयोजित विश्व टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण भारत के लिए मजबूरी नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता है।



कि अगले सात साल में 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा जोड़ने का भारत का लक्ष्य सही और शक्तिशाली इरादा है। उन्होंने कहा कि हाल ही जी-20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

(रा.प., 24.02.23)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर है कई चुनौतियां

भारत संचारी रोगों में वृद्धि के साथ उच्च रक्त चाप, कैंसर, एनीमिया, कुपौषण समेट स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधित संसद के स्थाई पैनल ने इनसे निपटने के लिए सरकार से स्वास्थ्य अनुसंधान बजट बढ़ाने की शिफारिश की है। पैनल ने कोरोना और उभरती चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश काफी कम है।

बीमारियों से निपटने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को अनुसंधान पर 1,300 करोड़ रुपए से अधिक तत्काल खर्च करने की आवश्यकता है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य अनुसंधान के बजटीय आवंटन को 2025-26 तक कुल स्वास्थ्य बजट का कम से कम पांच फीसदी और जीडीपी का 0.1 फीसदी तक बढ़ाना चाहिए।

(रा.प., 22.03.23)

सिकुड़ रहा है ओजोन परत का छेद

धरती पर रहने वालों के लिए पर्यावरण के बारे में राहत की खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन की परत का छेद अब सिकुड़ रहा है। यह छेद 1980 के दशक से चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन परत चार दशक के भीतर पूरी तरह ठीक होने की राह पर है।

जागरूकता है ऐसा मंत्र! भ्रष्टाचार का होगा अंत!!

पेरिस समझौते के तहत निर्धारित शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए जाबेर ने कहा कि यूएई भारत के उच्च वृद्धि-कम कार्बन के लक्ष्य में योगदान देने के लिए भारत के साथ साझेदारी के सभी अवसरों के साथ जुड़ना चाहेगा। जाबेर ने कहा

(रा.प., 24.02.23)

की ओर अग्रसर है। देश को विज्ञान और स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहन देना जरूरी है। नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए संस्थानों को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। तभी हम अंतिम छोर तक आर्थिक, सामाजिक विकास को गति देने में सफल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज विज्ञान के नवाचारों से वेस्ट मैनेजमेंट पर अत्यधिक कार्य करने की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट, बायोवेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आदि को कैसे हम ऊर्जा अथवा पुनः उपयोगी बना सकते हैं, इस पर मिशन इको सर्किल बना कर मजबूती से कार्य होना चाहिए।

मोदी ने यह बात राष्ट्रसंघ तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 2015 में विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया में 81वें स्थान पर था, आज टॉप तीन देशों में शामिल है। हम दुनिया के सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं।

(रा.प., 04.01.23)

टिकाऊ समाधान ढूँढ़ना आवश्यक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया संकट की स्थिति में है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अस्थिरता की यह स्थिति कब तक रहेगी। उन्होंने यह बात 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन में कही। मोदी ने खाड़ी, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभावों के साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता जताई।

उन्होंने विकासशील देशों के नेताओं से कहा, 'आपकी आवाज भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं।' उन्होंने कहा 'वक्त की मांग है कि हम सरल, पूरा करने योग्य और टिकाऊ समाधान ढूँढ़ें जो समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सके।' उन्होंने कहा भारत ने इस साल जी20 की अध्यक्षता शुरू की है। हमारा उद्देश्य वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ को बढ़ाना है।

युवाओं को बढ़ाने का बनाएं फ्रेमवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत दुनिया की ताकत बनने



राजस्थान सोलर में देश में सिरमौर है और बिंद एनर्जी उत्पादन में कर्नाटक गुजरात से आगे निकलने की तैयारी में है। यह बिजली में कोयला, लिग्नाइट व गैस पर निर्भरता घटने के संकेत हैं। इसके लिए 8.50 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये जमीन पर उतरेंगे तो मरुधरा खासकर पश्चिमी राजस्थान के पांच जिले देश के पावर हाउस नाम से जगमगा उठेंगे।

(रा.प., 27.02.23)



केंद्रीय बजट 2023-24

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार बजट ने अपने अमृत काल के दौरान एक समावेशी भारत की नींव रखी है, जिसमें न्यायपरस्ता, समानता के साथ विकास के उद्देश्यों को संतुलित किए जाने का प्रयास किया गया है। बजट में गरीबों और वंचितों का खास ध्यान रखते हुए उनके लिए तत्काल जरूरतों, मसलन मुफ्त अनाज, रहने के घरों का निर्माण, सस्ता इलाज, कौशल विकास व रोजगार सूजन एवं सभी अंत्योदय परिवारों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूँजीगत व्यय की अनिवार्यता को संतुलित किया गया है।



कृषि और किसानों के हक में बड़ा कदम

वित्तमंत्री ने बजट में खेती और किसानों से संबंधित योजनाओं के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि त्वरक कोष' की स्थापना सराहनीय कदम है। तीन साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। गोबरधन योजना से किसान व पशुपालक लाभान्वित होंगे। बजट में 20 लाख करोड़ रुपए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण देने का लक्ष्य है।

बजट में 10,787 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के लिए, करीब 2,200 करोड़ रुपए बागवानी की उपज बढ़ाने, 60 हजार करोड़ रुपए पीएम किसान समान निधि पर खर्च करने जैसे कई प्रावधान हैं। 20 लाख करोड़ तक किसानों को ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जा रहे हैं। यह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

जन स्वास्थ्य: अनुसंधान पर दिया जोर

वित्तमंत्री ने बजट में जन स्वास्थ्य के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछले बजट की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। देशभर में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इससे सभी राज्यों को फायदा मिलेगा। बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 36,785 करोड़ रुपए एवं 7,200 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए प्रावधान किया गया है।

कोविड-19 से मुकाबले के लिए टीके पर 220 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 517 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बजट में सरकार ने फार्मास्युटिकल में अनुसंधान और नवाचारों को 6 प्रोत्साहित करने पर खास ध्यान दिया गया है।

मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से इलाज सस्ता होगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक इनकी पहुंच हो सकेगी।

आधुनिक शिक्षा से होगी नींव मजबूत

केंद्र सरकार के बजट में स्कूली शिक्षा व साक्षरता के लिए 68,804.85 करोड़ रुपए तथा उच्च शिक्षा के लिए 44,094.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले बजट में डिजिटल शिक्षा को खास अहमियत दी गई थी। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बजट में बच्चों व युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने की घोषणा सराहनीय है। इसके लिए पंचायत व वार्ड स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव भी बजट में है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में मोबाइल एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए सौ लैब्स बनाने की भी घोषणा की गई है। इससे शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों की गुणवत्तापूर्ण किताबें आसानी से मिल सकेंगी। शिक्षण संस्थानों में भी संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। देश की शीर्ष शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए जाएंगे।

कौशल योजना से खुलेंगे रोजगार के द्वारा

आम बजट में कौशल विकास मंत्रालय के लिए 3,517.31 करोड़ रुपए आवंटित है। युवाओं को कौशल विकास योजना के माध्यम से सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर जुटाने पर जोर दिया गया है।

इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, उद्योग में साझेदारी और नए उद्योगों की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर राज्यों में खुलेंगे। इनमें विदेशों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एमएसएमई उद्योगों को मिला सपोर्ट

आम बजट में वाणिज्य एवं उद्योग जगत के लिए 48,169 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पूँजी का अतिरिक्त सपोर्ट मिलने से राहत मिली है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में 9,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा उन्हें ताकत देगी। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल-फ्री गारंटीड ऋण दिए जा सकेंगे। घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 915 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

घाटे से जु़ज़ते स्टार्टअप्स को भी सहायता के साथ आयकर में भी छूट दी गई है। कृषि स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। खाद्य प्रस्करण उद्योग के लिए 1530 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए 90 हजार करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है।

आधारभूत ढांचे से सुधरेगी आर्थिक सेहत

बजट में आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, सौर व पवन ऊर्जा संबंधी उपक्रमों आदि का बजटीय आवंटन 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 66 प्रतिशत की बढ़ोतारी की गई है। ग्रामीण और छोटे शहरों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया है।

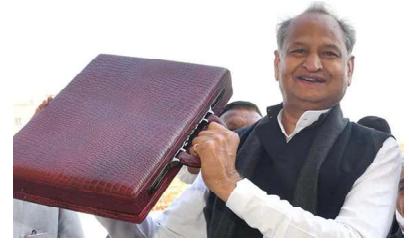
शहरी विकास पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान है। सार्वजनिक परिवहन में सुधार पर 75 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। यातायात को सुगम बनाने के मकसद से गति शक्ति योजना को अमल में लाया जाएगा। इससे सड़क, रेल एवं हवाई परिवहन को खास पहचान मिलेगी। पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा तंत्र की मजबूती के लिए भी कई काम होंगे।



राजस्थान राज्य बजट 2023-24

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखा। इस बार बजट में चुनावी साल होने और फिर से सरकार बनाने की चाह में किसानों को खुश करने के लिए मुफ्त बीज और बिजली देने जैसी कई घोषणाएं की गई हैं।

इसी तरह आमजन की सेहत के लिए भी मतदाताओं की नब्ज़ टटोलते हुए चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर लोगों को आस बनाई है। बजट मदों के तहत करीब-करीब पूर्व में जारी सभी योजनाओं में भी धन राशि बढ़ाते हुए उन्होंने दिल खोल कर राहतें बांटी। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ही सफाई देते हुए कहा भी है कि यह बजट चुनावी नहीं है। पिछले चार सालों से जीरो टैक्स वाला बजट दे रहा हूं....।



खेती किसानों के लिए सौगातों की झड़ी

इस बार प्रदेश के बजट में खेती और किसानों के फायदे के लिए 1,84,311.57 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। कृषि कनेक्शन में अब 2000 हजार यूनिट तक का उपभोग करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। पहले यह सीमा 1000 यूनिट थी। बजट में किसानों को 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित करने का प्रावधान रखा गया है। कृषि कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह राशि 5 हजार करोड़ थी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर 13,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर सर्टिफिकेशन यूनिट व टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। साथ ही 50 हजार किसानों को 5 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा भी बजट में है। सरकार के पिछले बजट के 11 मिशन में अब 12वां मिशन और जोड़ा गया है। इसके तहत युवाओं के लिए 'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन' की स्थापना होगी, यह एक सराहनीय कदम है। इससे युवा वर्ग का कृषि व इससे संबंधित व्यवसायों की ओर रुझान बढ़ेगा।

नब्ज़ पर रखा हाथ, चिरंजीवी देगी साथ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में मुफ्त की योजनाओं को ज्यादा अहमियत दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। दुर्घटना बीमा राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। इंडब्ल्यूएस परिवारों को भी अब चिरंजीवी बीमा का लाभ निःशुल्क मिलेगा। निःशुल्क जांच योजना के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

बचे हुए तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और खुलने पर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। बजट में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा जयपुर में एसएमएस व आरयूएचएस में सुविधाओं का विस्तार करने जैसे कई प्रस्ताव बजट में हैं।

आयुर्वेद चिकित्सालयों में भी सुविधाएं बढ़ाने, होयोपैथिक व आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का वादा बजट में किया गया है। उपजिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र व सेटेलाइट अस्पताल खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे।

शिक्षा के खुलेंगे द्वार, करेंगे सपने साकार

अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के साथ बालकों के लिए भी 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 26 राजकीय महाविद्यालय, 20 महिला महाविद्यालय खोले जाएंगे।

इसके अलावा बजट में 11 नए आईटीआई और 7 संचालित आईटीआई को सेंट्र ऑफ एक्सीलेंस बनाने और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नई ब्रांच शुरू करने और रिसर्च को बढ़ावा देने जैसी कई घोषणाएं हैं।

8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने, 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने और 300 विद्यालयों में नए विषय चालू करने से प्रारम्भिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी। स्कूलों में मिड- डे -मील और प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने से बच्चों को समुचित पोषण मिल सकेगा।

औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख

बजट में औद्योगिक विकास की बुनियाद को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रदेश के 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इकॉनोमिक जोन को विकसित करने पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उदयपुर में एयर कार्गो बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना का प्रस्ताव है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए सह कार्य स्थल बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना से अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे।

आधारभूत ढांचा होगा मजबूत

शहर से लेकर गांवों तक सड़कों का जाल बिछेगा। हर जिले की 5-5 महत्वपूर्ण सड़कों का विकास कराया जाएगा जिस पर 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्यारह सौ गांवों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से कच्ची सड़कों पर डामर की सड़क बिछेगी तथा हर गांव में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक किलोमीटर लम्बाई में इंस्टरलॉकिंग टाइल का जाल बिछाया जाएगा।

बजट में प्रदेश के 100 से ज्यादा शहरों में निकायों को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान दिया गया है। ड्रेनेज, सीवरेज और सौन्दर्योक्तरण के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के काम तेजी से होंगे। सस्ती बिजली के लिए नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 11,233 करोड़ रुपए परिवहन बेड़े को मजबूत करने पर खर्च किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव सराहनीय है, इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।



देश बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब

देश को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। देश में कम लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेटिव दिया जाएगा। इंसेटिव देने पर 17,490 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की ओर से समय-समय पर उठाए गए कदमों की दुनिया में

तारीफ हुई है। गौरतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पानी व सस्ती ऊर्जा की जरूरत है। भारत के पास दोनों संसाधन मौजूद हैं। देश में काफी लंबा समुद्र तट और सूरज की भरपूर रोशनी है। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा है, जो सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। इससे प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं।



(रा.प., 05.01.23)

मुफ्त की बिजली से होगा फायदा

प्रदेश के बजट के अनुसार कृषि कनेक्शन में अब 2000 यूनिट तक का उपभोग करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। अब 100 यूनिट का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का भी विद्युत शुल्क शून्य हो जाएगा।

बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में छूट का प्रावधान है। लेकिन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट अरबन सेस और इलेक्ट्रिसिटी इयूटी तो देनी ही पड़ेगी। इसमें सौ यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले हैं, फिक्स चार्ज अलग है। आंकड़ों को देखे तो राज्य में 1.54 करोड़ उपभोक्ताओं में से 1.19 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले एक करोड़ चार लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।

इनके सालाना करीब 5200 करोड़ रुपए के बिजली बिल भुगतान सरकार वहन करेगी। जबकि, बाकी 15 लाख घरेलू उपभोक्ता को हर साल बिल में 300 से 750 रुपए तक स्लेबवार बिल में छूट दी जाएगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 11.02.23)

फ्लैट में रहने वाले बनाएंगे बिजली

राज्य में 10 हजार बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग भी सोलर पैनल लगाकर बिजली

लागू होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी

देश में सबसे पहले राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। सौर ऊर्जा (सस्ती बिजली) से ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफायरनी, फर्टीलाइजर, सीमेंट, परिवहन, विमानन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों में होगा। प्रदेश में ही उत्पादन होने से दूसरे राज्यों से मंगाने की जरूरत नहीं होगी। वित्त विभाग ने अक्षय ऊर्जा निगम को पॉलिसी ड्राफ्ट में इसे जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए कई बड़ी कंपनियां पहले से ही होमर्क कर रही हैं। यदि ये प्लांट लगाती हैं तो ये पहली तीन कंपनियों में शामिल होकर बड़ी छूट का फायदा लेंगी। ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा फायदा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, उत्पाद भी सस्ते बनेंगे तथा भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में भी मददगार साबित होगा।

(रा.प., 01.03.23)

उत्पादन कर सकेंगे। फ्लैट की बालकनी में लगाने के लिए सोलर पैनल आएंगे। राजस्थान सोलर एसोसिएशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ फ्लेट्स में भी सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से बात की गई है। अभी कुछ बहुमंजिला इमारतों की छत पर सोलर पैनल है, लेकिन फ्लैट तक नहीं पहुंच पाए। प्रदेश में अभी 300 मेगावाट क्षमता के ही रूफटॉप सोलर पैनल लगे हैं।

इनसे 28 हजार बिजली उपभोक्ता जुड़े हैं। पर्यावरण के लिए यह बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्डिंग बायलॉज में भी ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर काम करने की अनिवार्यता है। इससे लोगों के बिजली बिल में कमी आएगी और खाली जगह का उपयोग भी हो सकेगा।

(रा.प., 25.01.23)

सरकारी महकमों में बकाया बिजली बिल

राज्य सरकार के सरकारी महकमों पर 1947 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं। इसमें 1218 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि स्ट्रीट लाइटों के बिलों से संबंधित है, जो नगरीय निकायों एवं पंचायतों पर बकाया है। बाकी राशि भी अन्य सरकारी विभागों में बकाया चल रही है। इससे बिजली

कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है और लगातार लोन लिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि निकायों और पंचायतों में बिजली बिलों की बकाया राशि को वर्तमान में माफ किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार की ओर से स्वायत्त शासन विभाग को जारी की जाने वाली अनुदान राशि से सीधे कटौती कर बिजली कंपनियों को भुगतान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(दै.भा., 14.03.23)

लगेगा फ्लूल सरचार्ज का झटका

कोयला खरीद के नाम पर एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं पर फ्लूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया गया है। उपभोक्ता को अप्रैल माह में जारी होने वाले बिल में 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। इसके जरिए डिस्कॉम 562 करोड़ रुपए वसूलेगा। प्रति उपभोक्ता के बिल में 150 से 600 रुपए का भार आएगा।

डिस्कॉम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कृषि व 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाले उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्हें सरकार सब्सिडी दे रही है। सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में फ्लूल सरचार्ज के रूप में अब तक बिल में औसतन 35 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार आ चुका है।

(रा.प., 25.03.23)



बूंद-बूंद बचाएं पानी, घट रहा भूजल

राजस्थान में पानी सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। जल संरक्षण के लिए सभी को एकसाथ मिलकर काम करना होगा। पानी की बूंद-बूंद को बचाना बेहद जरूरी है। पिछले मानसून में प्रदेश के 33 जिलों की भूमि को 10.96 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी मिला, लेकिन 16.55 अरब घन मीटर भूमि से निकाल लिया गया। प्रदेश में 2023 में बनी 302 ब्लॉक की रिपोर्ट डराने वाली है। क्योंकि इनमें 219 ब्लॉक अति दोहित है।

पिछले 10 साल में 21 जिलों में भूजल घटा है। जिलों में केवल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ही सुरक्षित हैं। 29 जिले दयनीय स्थिति में हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी 14.18 बीसीएम सिंचाई के लिए, 2.23 बीसीएम पानी पीने व अन्य डोमेस्टिक उपयोग और 0.14 बीसीएम इंडस्ट्रीज के लिए निकाल जा रहा है।

(दि. भा., 22.03.23)



राजस्थान में जल-जन अभियान शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू रोड के ब्रह्माकुमारीज संस्थान में जल-जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर दस हजार से अधिक लोगों ने जल संरक्षण की शपथ ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल-जन अभियान ऐसे समय पर शुरू हो रहा है, जब पानी की कमी को पूरे विश्व में संकट के रूप में देखा जा रहा है। जल संरक्षण सबसे बड़ा दायित्व है। जल रहेगा तभी कल रहेगा। इसके लिए सभी को मिलकर हर तरीके से प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि हम जल को देवता और प्रकृति को मां मानते हैं। हम भविष्य की चुनौतियों का समाधान खोज रहे हैं तो अतीत की चेतना को जागृत करना होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान जल संरक्षण का मॉडल बन कर उभर रहा है। (रा.प. एवं दि.भा., 17.02.23)

भूजल में घुला मिला यूरेनियम

राजस्थान में भूजल के बढ़ते दोहन की समस्या पहले से ही विकराल है। अब राज्य का भूजल रेडियो एक्टिव प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। प्रदेश के 28 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा अनुमत सीमा 0.03 एमजी प्रति लीटर से अधिक मिली है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की ताजा रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

चिकित्सकों के अनुसार ऐसा पानी पीने से लीवर से जुड़ी बीमारियां व कैंसर हो सकता है। विकृत बच्चे पैदा होने की भी आशंका रहती है। देश के 18 राज्यों के 187 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई

है। पिछले कुछ सालों से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हेलिबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे में यूरेनियम के भंडार होने के संकेत मिले हैं। इन राज्यों में भूजल यूरेनियम से सबसे ज्यादा संदूषित पाया गया है। भू वैज्ञानिक इसके अध्ययन में जुटे हैं। (रा.प., 13.01.23)

दूषित पानी का दंश झेल रहे हैं लोग

जयपुर शहर में हजारों लोग दूषित पानी का दंश झेल रहे हैं। जलदाय विभाग की एक रिपोर्ट इसका खुलासा करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में 20 से ज्यादा क्षेत्रों में आए दिन सुबह शाम दूषित पानी की आपूर्ति होती है। इन क्षेत्रों को इस हिसाब से अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है।

जानकारी के अनुसार किसी क्षेत्र में चार बार से ज्यादा दूषित पानी आने की शिकायतें पीएचईडी को मिलती हैं तो उस क्षेत्र को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। पानी की सप्लाई लाइन में लीकेज, सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने पर घरों में दूषित पानी पहुंचता है। जबकि जलदाय विभाग के इंजीनियर पुरानी लाइन बदलने और लीकेज सही करने के दावे कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। (रा.प., 06.02.23)

भूजल से जुड़े कानून में संशोधन जरूरी

संसदीय समिति ने सरकार से 140 साल पुराने उस कानून में संशोधन करने को कहा है, जो जमीन के मालिक को अपनी संपत्ति के नीचे के पानी पर पूर्ण नियंत्रण रखने और अपनी इच्छा के अनुसार भूजल का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

आधारभूत सेवा

संसदीय समिति ने इस विषय पर सरकार के जवाब को अस्वीकार करते हुए कहा कि कोई भी जल संसाधनों का दोहन करने और उसे प्रदूषित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जल संसाधन विभाग को भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 में संशोधन करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। (रा.प., 02.01.23)

नहीं मिल पा रहा पीने लायक पानी

दुनिया में हर चौथे व्यक्ति को पीने लायक पानी नहीं मिल पा रहा। विश्व जल दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट यह डरावनी तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल दुनिया में 26 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ सुरक्षित पेय जल नसीब नहीं है और दुनिया के 46 प्रतिशत लोगों की पहुंच बुनियादी स्वच्छता तक नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों में विश्व स्तर पर पानी का उपयोग लगभग एक प्रतिशत की दर से हर साल बढ़ रहा है। दुनिया की आबादी का औसतन 10 प्रतिशत हिस्सा पानी की गंभीर कमी वाले देशों में रहता है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 में दुनिया की शहरी आबादी में 93 करोड़ लोगों ने पानी की कमी का सामना किया। पानी के लिए संघर्ष करने वालों की ये संख्या 2050 तक 240 करोड़ हो सकती है। इन हालातों में फिलहाल अरबों लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। (रा.प., 23.03.23)

देश में पानी की किललत के आसार

देश को इस बार गर्मी में पानी की कमी के संकट से जूझना पड़ सकता है। सभी प्रमुख जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम पानी दर्ज किया गया है। इस बार सर्दियों में कम बारिश और फरवरी में रेकॉर्ड तोड़ तापमान ने मिट्टी की नमी को नुकसान पहुंचाया है। इससे एक तरफ किसानों पर बोझ बढ़ गया है तो दूसरी तरफ पेयजल जरूरतों पर असर पड़ने के आसार है।

केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सवा सौ से ज्यादा जलाशयों का मौजूदा जलस्तर 2022 को इसी अवधि में 92 प्रतिशत है। पिछले साल इन जलाशयों में 94.027 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी था, जबकि इस साल यह 86.45 बीसीएम है। (रा.प., 27.03.23)



बच्चों के नवाचार से होंगे सपने साकार

प्रदेश में स्कूली बच्चों के विचार (आइडिया) को सामने लाने और फिर उसे स्टार्टअप की शक्ति देने पर अब तेजी से काम होगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग यूनिसेफ के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की टीम तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में दो लॉन्च पैड (इन्क्यूबेशन सेंटर का छोटा रूप) खोले जाएंगे। यहां बच्चे अपने आइडिया को लॉन्च कर सकेंगे और डीओआईटी उसे स्टार्टअप की शक्ति देने के लिए सहयोग करेगा।

फिलहाल 1800 से ज्यादा स्कूलों के 30 हजार बच्चों को इससे जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। नवाचार में रुचि रखने वाले बच्चों को लॉन्च पैड में बताएंगे कि किस तरह स्टार्टअप बन सकता है। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो इन्क्यूबेशन सेंटर आपको गोद लेते हैं। आपके स्टार्टअप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी जरूरी मदद की जाएगी।

(रा.प., 17.03.23)

सरकार चुनने में बढ़ी महिला हिस्सेदारी

लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा, देश में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वर्ष 1971 से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या में 235.72 फीसदी की बढ़ोतारी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में, पहली बार मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से आगे निकल गया।

महिलाओं ने राजस्थान में भी अपनी निर्णयक भूमिका निभाई। राजस्थान में 2018 के चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67 था, वहीं पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.49 रहा। माना जा रहा है कि शिक्षा का बढ़ता स्तर व राजनीतिक जागरूकता इसकी मुख्य वजह है। देश की आधी आबादी की ओर से लगातार चुनावों में निर्णयक भूमिका निभाना लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है।

(रा.प., 05.01.23)

बंजर जमीन को बना दी हरितम ढाणी

चूरू जिले के सुजानगढ़ से सटे गांव गोपालपुरा की हरितमा ढाणी बेहद अनूठी है।

सरपंच सविता राठी और गांव की महिलाओं की जिद और जुनून ने सैकड़ों साल से गंदगी और उजाड़ से अटी बंजर जमीन को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। पिछले साल एक साथ एक दिन में यहां महिलाओं ने श्रमदान कर 5100 पौधे रोपे हैं।

यह ऐसी जगह है जहां राजस्थानी संस्कृति, परम्परा और संपदा को जिन्दा रखने की जिद की जा रही है। यह देखकर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसे डेजर्ट पार्क की तर्ज पर विकसित करने को आगे आया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए भी दिए हैं। अब यहां कैमल सफारी और ठेठ राजस्थानी खाने के व्यंजनों पर धूमधारी और अधूरे पड़े हैं।

सहित लोक कलाकार तक पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए झोपड़ियां भी बनाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी आने लगे हैं। (दै.भा., 23.01.23)

पीएम आवास योजना पर नाता प्रथा भारी

सरकारी सुविधाएं कई बार सामाजिक प्रथा-कुप्रथाओं के आगे दम तोड़ देती है। ऐसा ही मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आया है। योजना के तहत प्रदेश में बन रहे मकानों में से 4000 मकान पिछले एक साल से आधे-आधे पड़े हैं। इसका कारण काफी चौंकाने वाला है। नाता प्रथा में महिलाओं ने नया पति चुन लिया और पुराने परिवार का मकान अधूरा रह गया।

आदिवासी बहुल उदयपुर, बांसवाड़ा, झंगरपुर और प्रतापगढ़ में ऐसे मामले ज्यादा हैं। मसलन, उदयपुर में ऐसे करीब 400 मामले हैं। किसी ने एक तो किसी ने दूसरी और किसी ने तीनों किश्त लेने के बाद नाता विवाह कर लिया। ऐसे में प्रदेश में 48 करोड़ और उदयपुर में 4.80 करोड़ रुपए के आवास अधूरे पड़े हैं। यह अब जिला परिषद् के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। अफसर न बाकी किश्तें जारी कर पा रहे हैं और न ही पैसे बसूल पा रहे हैं। (दै.भा., 28.02.23)

महिलाएं गांवों को करेगी रोशन

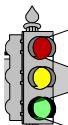
देश के अलग-अलग राज्यों की ग्रामीण समुदाय की 15 महिलाओं ने जयपुर के हरमाड़ा गांव स्थित बेयरफुट कॉलेज इंस्टीट्यूट नल में पांच महीने का सौर ऊर्जा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। ये महिलाएं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हैं।

हाल ही कॉलेज के एक समारोह में इन्हें सोलर इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। प्राप्त किए गए कौशल से ये महिलाएं अब अपने-अपने राज्य के गांवों को रोशन करने का काम करेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त ये महिलाएं आसानी से बिंदी सोलर टार्च, होम-लाइटिंग सिस्टम, सोलर एलईडी बल्ब आदि बनाकर उनका व्यवसाय कर सकेंगी। डिजिटल रूप से साक्षर ये महिलाएं भीम एप पर लेन-देन भी कर सकती हैं। (दै.भा., 03.02.23)



इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-भाल के लिए 500 प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर शुरू करने, संभाग मुख्यालयों पर 100 व जिला मुख्यालयों पर 50 इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल खोलने, रोडवेज बसों में दी जा रही छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी करने, सामूहिक विवाह अनुदान राशि बढ़ाने जैसी कई घोषणाएं महिला वर्ग को लाभान्वित करेंगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 11.02.23)



सड़क पर छोटी-सी असावधानी हमारे लिए और दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती है-सी.पी.जोशी

‘सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा’ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रतापगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ‘कट्स’ इंटरनेशनल और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलास्तरीय हितधारकों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय



संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सी.पी.जोशी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, निर्धारित गति में ही गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाते समय हैडफोन नहीं लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित चले और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

कार्यक्रम में ‘कट्स’ जयपुर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि भारत में चीन के बाद सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और इससे मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में अलग अलग कारणों से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना तीव्रगति से होती है। उन्होंने आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि भारत में पिछले दस सालों में लगभग पंद्रह लाख लोगों ने अपनी जिंदगी सड़क दुर्घटना में गंवाई। उन्होंने हाल ही प्रतापगढ़ जिले में घटित हृदयविदारक सड़क दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए शहर से गांवों तक अभियान चलाना चाहिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति को भी सक्रिय होने की जरूरत है।

परामर्श बैठक में पुलिस निरीक्षक (मोटर व्हीकल) दुर्गा शंकर जाट ने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नशे में ड्राइविंग करना, लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाना, सड़क पर

सड़क सुरक्षा पर खर्च होगा चालान राशि का एक हिस्सा

सड़क पर यातायात नियम तोड़ने पर एकत्र चालान राशि का एक हिस्सा सड़क सुरक्षा निधि में जाएगा। निधि का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में किया जाएगा। निधि का निर्माण सड़क सुरक्षा एक्ट के तहत किया जाएगा। इस बाबत बिल का ड्राफ्ट 4-5 महीने पहले किया जा चुका है। ड्राफ्ट पर आम जन से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। संभावना जर्ताई जा रही है कि इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में लाया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा निधि का उपयोग सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों में किया जाएगा। इसके तहत सुरक्षा योजना व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही सड़क सुरक्षा के उपकरणों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की स्वामित्व वाली सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छोटे सुधार कार्य भी इसी निधि से करवाए जाएंगे। ट्रोमा सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण में भी इस निधि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

(रा.प., 02.01.23)

सड़क सुरक्षा ! जीवन रक्षा !!

चलते हुए यातायात नियमों का पालन नहीं करना आदि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। यह देखा गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल होने और मरने वालों की सर्वाधिक संख्या युवा वर्ग की है, जो बिना हेलमेट पहने वाहन तेज गति से चलाते हैं।

उन्होंने मोटर वाहन

अधिनियम 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करना, शराब के नशे में वाहन चलाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, लापरवाही से और निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय सीट बैलट नहीं पहनना और ओवरलोडिंग आदि अपराधों के संबंध में सख्त प्रावधान किए गए हैं। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बस, ट्रेम्पों आदि की छतों पर बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।

‘कट्स’ मानव विकास केंद्र के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से अधिकतर को मरने से बचाया जा सकता है यदि घायल को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके लिए आम जनता में भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने गुड सेमेरिटन यानी ऐसा व्यक्ति जो दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को तत्काल चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता देता है को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परामर्श बैठक में राजकीय पी.जी.कॉलेज के सहायक प्रोफेसर एस.एम राय, सहायक जिला शिक्षा अधिकारी निधि बोहरा, महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन मदन गिरी गोस्वामी ने किया।

सड़क सुरक्षा के लिए बदलनी होगी मानसिकता

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सरकारें नियम बना सकती है, लेकिन उनका पालन जनता का दायित्व है। सड़क सुरक्षा वास्तव में तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सरकार के प्रयासों के साथ सभी लोग और सिविल समाज भी इस कार्य में सहयोग करें।

उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनता, विशेषकर युवाओं की मानसिकता को बदलना होगा। बिरला ने यह बात कांस्टीट्यूशन क्लब से एक कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले हुए कार्यक्रम में कही।

बिरला ने बताया कि हमारे देश में प्रति वर्ष 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। यातायात के नियमों का पालन करें तो हम स्वयं को तथा दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। (रा.प., 27.03.23)

उपभोक्ता फैसले

घर खरीददारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला

देशभर में लाखों लोग बिल्डरों की लेटलतीफी और बदनीयती के कारण घर खरीदने के लिए पैसा जमा कराने के बावजूद घर का कब्जा पाने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने घर खरीददारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि लोग सपनों के साथ घर खरीदते हैं, उन्हें घर के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। बिल्डर तय समय में कब्जा नहीं दे पाता है तो उसे खरीदार को मुआवजा देना होगा।

आयोग ने बैंगलूरु के एनडी डेवलपर्स द्वारा खरीददारों को समय पर घर का कब्जा नहीं दिए जाने को सेवा में कमी माना है और खरीददारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसले में कहा गया है कि कब्जा देने में देरी पर बिल्डर को कुल रकम का उतना फीसदी मुआवजा देना होगा जितना भुगतान में देरी होने पर उपभोक्ता से ब्याज के रूप में वसूलते हैं। आयोग ने 9 फीसदी सालाना ब्याज के साथ जमा कराई गई कुल राशि भी दो महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। यदि राशि दो माह में नहीं लौटाई तो पूरी रकम पर सालाना 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

(ग.प., 03.01.23)



वैवाहिक कार्यक्रम हुआ ही नहीं, रिसोर्ट लौटाए जमा राशि

जयपुर स्थित अंबाबाड़ी निवासी विजय सोनी ने अपने बेटे के 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 तक होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम के लिए 11 जुलाई 2020 को रिंजेंटा रिसोर्ट व रॉयल ऑर्चिड होटल्स, रणथंभौर, सर्वाई माधोपुर को 1.1 लाख रुपए जमा कराए थे। लेकिन कोविड काल में पूरे देशभर में लॉक डाउन रहा और वैवाहिक कार्यक्रमों पर कई तरह के प्रतिबंध थे। कोविड काल के चलते सरकार ने आयोजनों पर कोई रियायत भी नहीं दी। इसके चलते रिसोर्ट में होने वाला अपना कार्यक्रम उन्हें रद्द करना पड़ा। जब उन्होंने रिसोर्ट से अपनी जमा राशि वापस मांगी तो रिसोर्ट ने लौटाने का आश्वासन तो दिया लेकिन लौटाई नहीं।

हारकर उन्होंने रिसोर्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) जयपुर में परिवाद दर्ज कराया और कहा कि जमा राशि नहीं लौटाना अनफेयर ट्रेड ऐक्टिव्स व सेवा दोष है। मामले की सुनवाई पर आयोग ने विजय सोनी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने रिंजेंटा रिसोर्ट व रॉयल ऑर्चिड होटल्स को उनकी जमा कराई राशि 1.1 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही जमा राशि पर परिवाद दायर करने की तिथि 14 मार्च 2022 से नौ फीसदी ब्याज देने के लिए कहा है। आयोग ने सेवा दोष होने पर रिसोर्ट पर 8000 रुपए हर्जाना भी लगाया है।

(दै.भा., 26.03.23)

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2023

जरूरी है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना

उपभोक्ता संस्था 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में यह उभर कर सामने आया कि आज अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं विश्व स्तर पर गहरे होते जा रहे ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, जिसका कमज़ोर उपभोक्ताओं पर खासतौर पर अनकहा प्रभाव पड़ रहा है।

संगोष्ठी में 'कट्स' के पॉलिसी एनालिस्ट आकाश शर्मा ने बताया कि आज के समय में स्वच्छ ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। ऊर्जा की हर क्षेत्र में खपत बढ़ती जा रही है। ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्रोतों से हमारा पर्यावरण प्रदूषण तो लगातार बढ़ ही रहा है साथ ही संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इन सबसे निजात पाने के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक उपभोक्ताओं की पहुंच जरूरी है। यह विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभाने में सहायक होगी।

संगोष्ठी के प्रारंभ में 'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना ने 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' मनाने, उसके मुख्य उद्देश्यों, उपभोक्ता अधिकारों और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' 2023 का विषय 'स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' है। संगोष्ठी में मौजूद प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की अहमियत पर अपने विचार खेले।



स्वेच्छा: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नका उक्सान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: गण्डू

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.228 2821

फैक्स: 228 2485, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

यहां भी दिल्ली, कोलकाता और चिनाईडग़ (भारत); लुसाका (जान्बिया); नैराबी (केन्या); आकरा (याना); होर्नेर्स (वियतनाम); बिनेवा (स्विटजरलैंड) और वांशिगंग डी.सी. (यूएसए)